Economic Partnership Agreement between India and Japan

(भारत और जापान के बीच आर्थिक साझेदारी समझौते)

Dr. Rajesh Maurya
Assistant Professor Economics,
Government Nehru College, Sabalgarh District Morena
Email-id:- dr.rajeshmourya1973@gmail.com

DOI: 10.52984/ijomrc4204

सार:-

सामान्य शब्दों में, आर्थिक साझेदारी समझौते, वह होते हैं, जिसमें दो या दो से, अधिक, देश बिना सीमा शुल्क या टेरिफ के, अंतरराष्ट्रीय द्विपक्षी व्यापार को, संचालित करते हैं। यह समझौते, विशेष रूप से, एक कमजोर और दूसरी मजबूत अर्थव्यवस्था, के बीच होते हैं। आर्थिक साझेदारी समझौते, किसी भी देश की, अर्थव्यवस्था में, आर्थिक वृद्धि और विकास को, बढ़ावा देते हैं। यह समझौता, एक प्रकार से, कानूनी रूप से, बाध्यकारी समझौता होता है, जिसमें दोनों देश, हस्ताक्षर करके, व्यापार को, आरंभ करते हैं। इन समझौते की, शुरुआत, उसे समय हुई थी, जब यूरोपीय संघ ने, एसीपी (अफ्रीकन, कॅरीबीयन एवं पेसिफिक) देश, के साथ, मुक्त व्यापार की, परिकल्पना, के साथ, द्विपक्षीय व्यापार को, प्रोत्साहित किया जाता था।

एशिया महाद्वीप में, स्थित, दो देश, भारत- जापान के, बीच, एशियाई आर्थिक एकीकरण ,के लिए, एकजुट हुए हैं। हालांकि, यह एकीकरण, काफी रणनीतिक जटिलता, के माहौल में, विकसित हुए, लेकिन फिर भी, एशिया महाद्वीप की, दो आर्थिक शक्तियां, भारत- जापान आर्थिक एकीकरण, के लिए, तीव्र गति से उभरकर आई है। यदि हम, इन दोनों देशों, के बीच, आर्थिक संबंधों की, बात करें, तो यह पता चलता है कि, वर्ष 1958 से, भारत और जापान, के बीच, आर्थिक सहायता, के रूप में, यह संबंध कायम रहे हैं। लेकिन इन दोनों, देशों में, आर्थिक संबंधों या द्विपक्षीय व्यापार में, रफ्तार, उसे समय आई, जब

भारत में, सन 1990-91 में, आर्थिक सुधार कार्यक्रमों, के तहत, वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण की, नीति अपनाई थी। तब से, भारत में, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, के रूप में, अनेक जापानी कंपनिया, मारुति, सुजुकी, पैनासोनिक आई और अपने पैर जमाने, शुरू कर दिए थे। लेकिन आर्थिक साझेदारी समझौते का, शुभारंभ फरवरी 2011 से, हुआ था, जिसके तहत, दोनों देशों, भारत- जापान ने, व्यापार बढ़ाया, विशेष रूप से, सीमा शुल्क या टेरिफ की, दरों को, कम या समाप्त करने का, निर्णय लिया और द्विपक्षीय व्यापार को, आरंभ किया था।

यह शोध पत्र, भारत और जापान, के बीच, आर्थिक साझेदारी समझौते, पर आधारित है। जिसमें हम, आर्थिक साझेदारी समझौता, क्या होता है?, को समझते हुए, यह जानने या समझने का, प्रयास करेंगे कि, भारत और जापान, के बीच, कौन-कौन सी आयत- निर्यात मदों पर, समझौता हुआ है और सीमा शुल्क या टेरिफ, की कौन-कौन सी, दरें निर्धारित की हैं? ।

मुख्य बिंदु:- ***आर्थिक संबंध, एशियाई आर्थिक एकीकरण, आयात, निर्यात, मदे।***

प्रस्तावना:-आप, हम, सभी लोग, यह बात अच्छी तरह से जानते व समझते हैं कि, अब तक, दुनिया में, दो विश्व युद्ध हो चुके हैं, जिनमें व्यापक पैमाने पर, जनहानि, के साथ-साथ, अर्थव्यवस्थाएं भी बर्बाद हो चुकी थी, जिन्हें पटरी पर, लाने या पुनरुत्थान हेतु, एक नई अवधारणा का, जन्म हुआ था। जिसे, एक दूसरे, के संदर्भ में, सहयोग या अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक विकास हेतु, आर्थिक साझेदारी समझौता, कहा जाता है। **एक वेबसाइट के अनुसार-**द्वितीय विश्व युद्ध, के परिणाम स्वरुप, ध्वस्त हुई, अर्थव्यवस्थाओं को, पुनः पटरी पर लाने, के लिए, एक बहुपक्षीय मंच पर, टैरिफ और व्यापार पर, एक सामान्य समझौता, गठित किया गया।(1) इसीलिए इसे व्यापार सौदो पर, अंतिम रूप देने के लिए, एक मार्गदर्शक दस्तावेज माना जाता है।

सामान्य शब्दों में, आर्थिक साझेदारी समझौता, वह है, जिसके अंतर्गत दो या दो से, अधिक देश,

मिलकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या द्विपक्षीय संबंधों, के द्वारा, अपने-अपने देश की, अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक विकास को, शीर्ष पर, पहुंचने का, काम करते हैं। इन देशों में, एक विकसित और दूसरा विकासशील देश, शामिल होते हैं। **लो.इनसाइडर डिक्शनरी के अनुसार-**आर्थिक साझेदारियां, एक ऐसी साझेदारियां हैं, जिसके अंतर्गत, तकनीकी सहायता, से लेकर, वाणिज्यिक समझौते और निवेश निधि को, जोड़ने का, कार्य किया जाता है।(2) जिनका उद्देश्य, उत्पादक संगठनों और अन्य मूल्य श्रृंखलाओं, के बीच, ठोस एवं पारस्परिक रूप से, लाभप्रद संबंध बनाना है।

एशिया महाद्वीप में, स्थित देश, भारत और जापान, आर्थिक साझेदारी समझौता, के क्षेत्र में, एक एशियाई, आर्थिक शक्ति, के रूप में, उभर कर आए हैं। हालांकि, इन दोनों देशों, के बीच, एशियाई आर्थिक एकीकरण, काफी रणनैतिक जटिलता, के माहौल में, विकसित हुए हैं। लेकिन फिर भी, जिस तरह से, भारतीय अर्थव्यवस्था, विश्व में, तेजी से, आगे बढ़ रही है और जापान तकनीकी, के क्षेत्र में, तीव्र गति से, आगे आया है, उसे ध्यान में, रखते हुए, यह कहा जा सकता है कि, भविष्य में, ये दोनों देश, एक बड़े रणनीतिक, विशेष रूप से, आर्थिक क्षेत्र में, खिलाड़ी के रूप में, उभरकर आ सकते हैं। यदि, हम भारत और जापान, के बीच, आर्थिक एकीकरण या जुडाव की, बात करते हैं तो, यह पता चलता है कि, **भारत सरकार द्वारा, संचालित किए गए, आर्थिक सुधार कार्यक्रम, जोकि सन 1990-91 से आरंभ हुआ था, में पूर्व की, ओर देखो, नीति के साथ, शुरू हुआ था।(3)** और आज, यह संबंध (आर्थिक साझेदारी) तीव्र गति से, शीर्ष स्थिति में, पहुंच गया है।

यह शोध पत्र, भारत-जापान, के बीच, आर्थिक साझेदारी समझौता पर आधारित है, जिसमें, हम यह समझने व जाननें का, प्रयास करेंगे कि, आज भारत-जापान, के बीच, आर्थिक एकीकरण या जुड़व की, क्या स्थिति है?, आदि।

अध्ययन के उद्देश्य

मैंने, इस शोध पत्र को, पूर्ण करने के लिए, निम्नलिखित उद्देश्यों का, निर्धारण किया है।

1. आर्थिक साझेदारी समझौता, क्या होता है?, को समझना।
2. भारत और जापान, के बीच, आर्थिक साझेदारी समझौते को, समझना।

अध्ययन की आवश्यकता

वर्तमान समय में, दो या दो से, अधिक देशों, के बीच, अपना-अपना आर्थिक विकास सफलतापूर्वक, पूर्ण करने के लिए, आर्थिक साझेदारी समझौता, नामक नीति को, अपना रहे हैं?, इस दृष्टि से, भारत-जापान जैसे, देशों ने, मिलकर, आर्थिक एकीकरण या जुड़ाब, के लिए, द्विपक्षीय व्यापार पर, विशेष रूप से, टेरिफ की, कम दर या समाप्ति, के संदर्भ में, हस्ताक्षर किए हैं। अब सवाल, यह उठता है कि, भारत ने, जापान के साथ, कौन-कौन से, क्षेत्र में, समझौता किया है?, क्या इस नीति को, स्वीकार करने से, लाभ हुआ है?, और कितना प्रतिशत, आदि सवालों, के जवाब, प्राप्त करने के लिए, आर्थिक साझेदारी समझौते का, अध्ययन करना अति-महत्वपूर्ण है? विशेष रूप से, अर्थव्यवस्था का, विकास और आर्थिक विकास, के संदर्भ में, आदि।

अध्ययन की सामग्री,

यह शोध पत्र, पूर्ण रूप से, द्वितीय संबंधों, पर आधारित है, जिसे पूर्ण करने के लिए, मैंने विभिन्न समाचार पत्रों, पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों, शोध जर्नलों और इंटरनेट, पर उपलब्ध, विभिन्न वेबसाइटों से, सामग्री प्राप्त की है।

आर्थिक साझेदारी समझौता

सामान्य शब्दों में, आर्थिक साझेदारी समझौता, दो या दो से, अधिक, देशों के बीच, अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक विकास हेतु, हस्ताक्षर करके, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, प्रोत्साहित करना है। वर्तमान में, यह (आर्थिक साझेदारी समझौते) अवधारणा, काफी लोकप्रिय हो चुकी है। आज इस 21वीं सदी में, लगभग सभी महाद्वीप जैसे:-एशिया, यूरोप, अफ्रीका आदि। के देशों में, काफी

क्रियाशील हो चुकी है, क्योंकि आर्थिक एकीकरण एवं आर्थिक प्रतिस्पर्धा हेतु, अधिक से अधिक देश, एकजुट हो रहे हैं।

आर्थिक साझेदारी समझौते की, अवधारणा, के अंतर्गत, यह विशेष रूप से, ध्यान रखा गया है कि, इसमें (आर्थिक एकीकरण) **एक कमजोर तथा दूसरी मजबूत अर्थव्यवस्था, होनी चाहिए, ताकि कमजोर अर्थव्यवस्था, अपने आर्थिक विकास को, प्रोत्साहित कर सके और मजबूत अर्थव्यवस्था को, वास्तविक लाभ प्राप्त हो सके।(4)** यह अवधारणा, दुनिया के विभिन्न देशों, द्वारा इसलिए भी, अपनाई जा रही है, जिससे कि, विश्व में शांति स्थापित करके, दोनों देशों में, जीवन यापन करने वाले, लोगों, के जीवन स्तर को, उच्च स्थिति में पहुंचा जा सके।

आर्थिक साझेदारी समझौते की, कार्य प्रक्रिया, के अंतर्गत, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, के तहत, जिसे मुक्त व्यापार भी कहते हैं, आयात-निर्यात, की जाने वाली वस्तुओं व सेवाओं पर, किसी भी, प्रकार का, सीमा शुल्क या टेरिफ लागू नहीं होता है। अर्थात इसके अंतर्गत, एक प्रकार से, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, के मार्ग में, आने वाली बाधाओ को, समाप्त करने का, प्रयास किया जाता है, ताकि उत्पादकों और उपभोक्ताओं को, लाभ प्राप्त हो सके, जैसा की, **एक वेबसाइट (www.investopedia.com) में उल्लेख किया गया है कि-**आर्थिक साझेदारी समझौते, जिसे आर्थिक एकीकरण भी, कहा जाता है, में उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों, दोनों के लिए, लागत कम होती है और इसमें शामिल देशों में, व्यापार। की मात्रा में वृद्धि होती है।(5) आर्थिक एकीकरण को, कभी-कभी, क्षेत्रीय एकीकरण भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें (आर्थिक एकीकरण) दूर-दराज स्थित देश के, साथ-साथ, पड़ोसी देश भी, शामिल होते हैं। इस प्रकार पड़ोसी देशों के, शामिल होने से, आर्थिक, के अलावा, राजनीतिक समन्वय भी बढ़ता है।

आर्थिक साझेदारी समझौते या आर्थिक एकीकरण, के समर्थन या अर्थशास्त्री या विशेषज्ञ, इसके

(आर्थिक एकीकरण) 7 चरणों को, परिभाषित करते हैं। **जैसे:-एक मुक्त व्यापार क्षेत्र, एक तरजीही व्यापार क्षेत्र, एक सीमा शुल्क संघ, एक सामान्य बाजार, एक आर्थिक संघ, एक आर्थिक एवं मौद्रिक संघ और राजकोषीय नीति के, पूर्ण संमजस्य तथा पूर्ण मौद्रिक संघ आदि।(6)**

आर्थिक साझेदारी समझौते, के अंतर्गत, दो देशों, के बीच, जो भी समझौता होता है, उसमें **गैर-टैरिफ उपाय या टेरिफ में कटौती, के अलावा, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार तथा प्रतिस्पर्धा जैसे व्यापार संबंधी, पहलुओं पर, ध्यान आकर्षित किया जाता है।(7)** लेकिन व्यापार संबंधित, पहलुओं में, इस बात का, विशेष ध्यान रखा जाता है कि, निवेश या व्यापार हेतु, होने वाले समझौता से, सबसे अधिक, लाभ, विकासशील देशों को प्राप्त हो, जिससे यह देश भी, वैश्विक अर्थव्यवस्था के, साथ सतत आर्थिक विकास, के संदर्भ में, समाहित या एकीकृत हो सकें।

संपूर्ण विश्व में, वर्तमान में, विभिन्न देशों, के बीच, जो आर्थिक साझेदारी समझौते की, अवधारणा तेजी से, **लोकप्रिय होती जा रही है, उसका कारण, रोजगार में वृद्धि, गरीबी में कमी, नवप्रवर्तन या प्रौद्योगिकी का, व्यापक पैमाने पर, हस्तांतरण और निर्यात विविधीकरण है।(8)** यह (निर्यात विविधीकरण) का, मतलब, सभी प्रकार की, वस्तुओं एवं सेवाओं के, आयात-निर्यात से है। हालांकि, आर्थिक साझेदारी समझौते से, विकासशील देशों को, अधिक लाभ की, संभावनाएं हैं, लेकिन फिर भी, इससे भी, इनकार नहीं किया जा सकता है कि, इस क्षेत्र में, अनेक चुनौतियां एवं जोखिम है। सबसे पहले, इससे घरेलू उत्पादकों, के लिए, प्रतिस्पर्धा की, स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसका परिणाम, यह होगा कि नौकरियां कम होने से, बेरोजगारी की, समस्या सृजित हो जाएगी और मजबूत अर्थव्यवस्था वाले, देश को, अधिक लाभ उत्पन्न होने लगेगा। इसीलिए आर्थिक नीति-निर्माताओं एवं अर्थशास्त्रियों का, कहना है कि (इसे आर्थिक साझेदारी समझौता) सावधानी पूर्वक, काफी विचार-विमर्श तथा जिन क्षेत्रों में, जरूरत है, उन्ही में, इसे स्वीकार करना चाहिए।

विश्व के, विभिन्न अर्थशास्त्रियों एवं विशेषज्ञों ने, आर्थिक साझेदारी समझौता की, परिभाषा को, इस प्रकार प्रस्तुत किया है।

फैक्टसीट नंबर 1 (मार्च 2007) के अनुसार-यह (आर्थिक साझेदारी समझौते) एक प्रकार से, मुक्त व्यापार समझौते हैं, जिनका उद्देश्य, अफ्रीकन, कैरेबियन एवं पेसिफिक तथा यूरोपीय संघ, के बीच, एक मुक्त व्यापार के, निर्माण की, परिकल्पना करना है। जिसका मतलब यह है कि, अब, इन दोनों, देशों के बीच, आयात-निर्यात पर, कोई भी, शुल्क या टेरिफ नहीं लगेगा।(9)

एल.ज़म्फिर (2018) में अपने लेख में स्पष्ट किया है कि-आर्थिक साझेदारी समझौते, एक प्रकार से, विकास उन्मुक्त असममित समझौते हैं, जो अफ्रीकन, कैरेबियन एवं पेसिफिक देश को, उनके सतत आर्थिक विकास, क्षेत्रीय एकीकरण और विश्व बाजारों में, एकीकरण को, बढ़ावा देने के लिए, महत्वपूर्ण लाभ व सुरक्षा, उपाय प्रदान करते हैं।(10)

एक वेबसाइट (www.abip.org.br.) के अनुसार-विश्व में, विभिन्न देशों द्वारा, अपनाये जा रहे, आर्थिक साझेदारी समझौते, एक प्रकार से, अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते हैं, जिनका उद्देश्य, भाग लेने वाले, देशों के बीच, आर्थिक वृद्धि व विकास को, बढ़ावा देना है।(11)

उपरोक्त परिभाषाओं, के आधार पर, यह कहा जा सकता है कि, आर्थिक साझेदारी समझौते, दो या दो से, अधिक, देशों के, बीच, एक मुक्त व्यापार समझौता है, जिसका मतलब यह है कि, अब दोनों देशों, के बीच, होने वाले आयात-निर्यात की, वस्तुओं व सेवाओं पर, किसी भी प्रकार का, सीमा शुल्क या टेरिफ नहीं लगेगा।

भारत और जापान

शोध पत्र के इस भाग में, हम भारत और जापान, के बीच, होने वाले आर्थिक साझेदारी समझौते को, समझने का प्रयास करेंगे।

भारत और जापान, के बीच, इस आर्थिक साझेदारी समझौते में,

सर्वप्रथम हम, भारत-जापान, के बीच, आर्थिक एकीकरण या जुड़वा, के ऐतिहासिक पक्ष पर, दृष्टि डालेंगे।

भारत और जापान, के बीच, आर्थिक जुड़ाव, के रूप में, पहला प्रमाण, **सन 1958 में मिलता है, जब जापान ने, भारत को, विदेशी सहायता, के रूप में, अपनी मुद्रा अर्थात येन में ऋण प्रदान किया था। यह येन मुद्रा में, 95% था।(12)** लेकिन यह संबंध, आर्थिक उतार-चढ़ाव की, स्थिति में रहे थे। ऐसा अनुमान है कि, सन 1970 में, रणनीतिक अभिसरण की, कमी तथा 1980 में, जापान में, चीन की बढ़ती हुई, रूचि ने, दोनों देशों (भारत-जापान), के बीच, कमजोर आर्थिक व राजनीतिक संबंध रहे थे। इसके बाद, जब भारत ने सन 1998 में, परमाणु परीक्षणों को, अंजाम दिया तो, जापान ने, अपना आर्थिक सहायता कार्यक्रम। निलंबित कर दिया था।

भारत और जापान, के बीच, आर्थिक व राजनीतिक संबंधों में, सुधार का, पता, सन 2000 के, दशक से, लगाया जा सकता है। यह वह दशक था, जिसमें इन दोनों (भारत-जापान) देश, के बीच, बदलाव आना आरंभ हो गया था और वर्ष 2003 के, बाद से, भारत जापानी, आर्थिक अनुदान का, सबसे बड़ा, प्राप्तकर्ता बन गया था। जिसका औसत **वर्ष 2008 से, 2012, के बीच, सालाना लगभग 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।(13)** इसके बाद, भारत और जापान के बीच, विदेशी निवेश प्रभाव में, तेजी से वृद्धि हुई और अनेक ऑटोमोबाइल्स कंपनियों जैसे:- सुजुकी, मारुति, पैनासोनिक आदि ने, भारत में, अपनी जड़े जमानी शुरू कर दी थी। तथा धीरे-धीरे, इन कंपनियों ने, हमारे देश में, प्रतिष्ठा हासिल कर ली थी।

भारत और जापान, के बीच, आर्थिक साझेदारी समझौता, **16 फरवरी 2011 में, हस्ताक्षर किए गए और 1 अगस्त 2011 से, लागू हुआ था।(14)** इन दोनों, देशों के, बीच, हुए इस समझौते को, अब तक का, सबसे व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता माना जा रहा है, जिसमें दोनों देशों, के बीच, लगभग 90% से, अधिक वस्तुओं व सेवाओं का, द्विपक्षीय व्यापार शामिल है। इस समझौते में,

आर्थिक गलियारे, बुनियादी ढांचा, स्वच्छ ऊर्जा, स्मार्ट शहर, कौशल विकास, खाद्य प्रसंस्करण तथा परिवहन, के विकास में, 33.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के, निवेश का, वादा किया गया है।(15) जापान की, भारत में, बढ़ती हुई भागीदारी, के पीछे, का, कारण भारत की, विशाल आबादी है, जोकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में, मांग में, तीव्रगति को, प्रोत्साहित करती है। इस दृष्टि से, **भारत-जापान का, पांचवा सबसे बड़ा, निर्यात बाजार बन गया है।(16)**

भारत और जापान, के बीच, आर्थिक साझेदारी समझौता में, जो करक महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, वह निम्नलिखित है।

- संपूर्ण विश्व में, जापान, एक श्रम दुर्लभ एवं पूंजी प्रचुर देश है, जबकि भारत, एक समृद्ध व कुशल मानव पूंजी का, आधार है, जोकि दोनों देशों के, लिए, लाभदायक सिद्ध हो सकता है।
- सूचना व संचार प्रौद्योगिकी, के क्षेत्र में, दोनों देश, उन्नत स्थिति में हैं। भारत की, ताकत सॉफ्टवेयर में है, जबकि जापान हार्डवेयर क्षेत्र में, उत्कृष्टता प्राप्त है, जो द्विपक्षीय व्यापार, के क्षेत्र में, सकारात्मक सिद्ध हो सकते हैं।
- भारत में, कच्चे माल एवं खनिजों की, प्रचुर मात्रा विनिर्माण क्षेत्र में, अहम साबित हो सकती है, जबकि जापान पूंजी में, अग्रणी होने से, दोनों देश, भारत-जापान, आर्थिक सहायचारी समझौते, के क्षेत्र में, महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं।

भारत और जापान, के बीच, आर्थिक साझेदारी समझौते को, सफल बनाने के लिए, दोनों देशों ने, अपनी-अपनी टैरिफ दरों में, कटौती करने का, फैसला लिया है। इसमें, **भारत ने, तत्काल टैरिफ कटौती के लिए, 17.4% टैरिफ लाइनों की, पेशकश की है, जबकि जापान ने, शून्य शुल्क के लिए, 87% टैरिफ लाइनों की, पेशकश की है।(17)**

भारत जापान, के बीच, आर्थिक साझेदारी समझौते में, विशेष रूप से, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश शामिल है, जिसमें दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा जैसी उच्च दृश्यता वाली प्रमुख योजनाएं शामिल हैं। इस योजना में, यह कहा गया है कि, इसमें 92 बिलियन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, आकर्षित किया जाएगा, जोकि बंदरगांहो, उच्च गुणवत्ता वाले भौतिक ढांचा, सामाजिक बुनियादी ढांचे, पर औद्योगिक संपदा आदि। आर्थिक घटकों, के विकास हेतु, होगा। जापानी सरकार ने**, इस परियोजना (दिल्ली-मुंबई औद्योगिक) के लिए, अगले 5 वर्षों में, 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, के संयुक्त सार्वजनिक एवं निजी निवेश की, घोषणा की है।(18)** इस तरह, यह निवेश, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों, के निर्माण में, एक बड़े महत्व को, दर्शाता है।

भारत-जापान, के आर्थिक साझेदारी समझौता में, जापान की, अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन एजेंसी भी, शामिल है। **जिसने वर्ष 2003-4, के बाद से, भारत सरकार को, सबसे बड़ी ऋण सहायता, प्रदान की है, और वर्ष 2010 तक, लगभग 58 परियोजनाएं, इसी एजेंसी, के सहयोग से, क्रियान्वित की जा रही है।(19)** इस एजेंसी द्वारा, इन परियोजनाओं को, पूर्ण करने के लिए, प्रतिबद्ध ऋण की, राशि, यु.एस.डी. 15 बिलियन निर्धारित की है, जबकि जापान की, संचायी आधिकारिक ऋण सहायता, भारत के लिए, 2010 में, यु.एस.डी. 41 बिलियन थी। इस ऋण सहायता में, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में, **बिजली, पुल, जल आपूर्ति, शहरी परिवहन और पर्यावरण, स्वच्छता, वन तथा बुनियादी ढांचा, जैसे क्षेत्र शामिल हैं।(20)**

भारत-जापान, के बीच, आर्थिक साझेदारी समझौते, के संबंध में, यह कहा जा रहा है कि, इस समझौते से, सबसे अधिक कपड़ा और मसाला निर्यातकों को, लाभ होगा, क्योंकि इन उत्पादों पर, आरंभ से ही, **टेर्रिफ या शुल्क समाप्त हो जाएगा। अर्थात 90% शुल्क या टेर्रिफ समाप्त किया जाएगा।(21)** इस बढ़ती हुई, साझेदारी से, भारत-जापान, दोनों को, संयुक्त रूप से, लाभ प्राप्त होगा।

भारत और जापान, के बीच, आर्थिक साझेदारी समझौता, नवीनतम वर्ष अर्थात वर्ष 2022 में भी, संचालित है। **मार्च 2022 में, जापान, के प्रधानमंत्री श्री फुमियों किशिदा, भारत की, यात्रा पर, आए, जिसमें, दोनों देशों, के प्रधानमंत्री (भारत-जापान) ने, अगले 5 वर्षों में, जापान से, भारत में, 5 ट्रिलियन जापानी येन के, सार्वजनिक एवं निजी निवेश का, इरादा व्यक्त किया है।(22)** इस निवेश के तहत, वर्ष 2022-23 में, भारत का, जापान, के साथ, द्विपक्षीय व्यापार, कुल 21.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है।(23)

भारत-सरकार के, वाणिज्य मंत्रालय के, आंकड़ों के अनुसार, भारत और जापान, के बीच, आयात-निर्यात की, कुल धनराशि, पिछले 5 वर्षों में, इस प्रकार रही है। जिसे, एक तालिका में, समझाने का, प्रयास किया गया है।

भारत-जापान के बीच पांच वर्षों में आयात-निर्यात की कुल धनराशि।

क्र.	**वर्ष**	**भारत का जापान को निर्यात** (अमेरिकन बिलियन डॉलर)	**भारत का जापान से आयात** (अमेरिकन बिलियन डॉलर)	**कुल द्विपक्षीय व्यापार** (अमेरिकन बिलियन डॉलर)
1.	2018-19	4.86	12.77	17.63
2.	2019-20	4.52	12.43	16.95
3.	2020-21	4.43	10.9	15.33
4.	2021-22	6.18	14.39	20.57
5.	2022-23	5.46	16.49	22.33

Source:-Department of Commerce, Govt. of India.

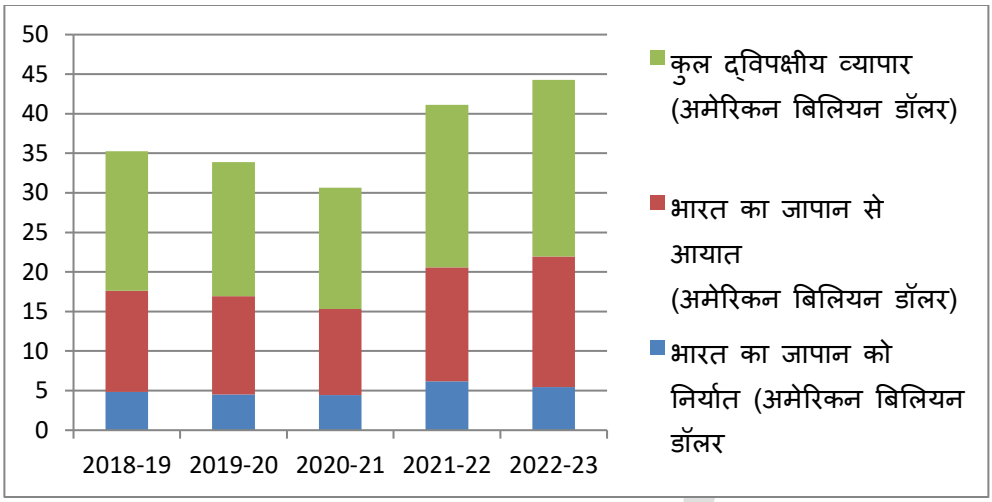

भारत जापान आर्थिक साझेदारी समझौते के तहत नवीनतम वर्ष अर्थात 2021-22 बार 2022-23 में जिन वस्तुओं का सेवाओं का निर्यात किया गया उनमें से सर्वश्रेष्ठ 10 निर्यात वस्तुओं व सेवाओं को तालिका में दर्शाया गया है।

भारत द्वारा जापान को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं में 10 मदों का विवरण।

क्र.	एच.एस.कोड	मदों का विवरण	धन राशि मिलियन डॉलर में वर्ष 2021-22	धन राशि मिलियन डॉलर में वर्ष 2022-23
1.	29	कार्बनिक रसायन	696.05	734.18
2.	3	मछली और क्रस्तेसिउस, मोलस्क और अन्य जलीय जीव	433.24	443.76
3.	84	परमाणु रिएक्टर, बॉयलर मशीनरी, यांत्रिक उपकरण	478.85	430.77

4.	87	रेलवे या टर्म्बे रोलिंग स्टॉक, अन्य वाहन	328.71	405.14
5.	71	प्राकृतिक या संबंधित मोती, कीमती, अर्ध कीमती पत्थर या उससे बनी वस्तुएं, नकली आभूषण।	394.43	351.29
6.	27	खनिज, इधन, खनिज, तेल और उनके उत्पाद, बिट्यूमिनस पदार्थ, खनिज	981.8	331.82
7.	85	विद्युत, मशीनरी उपकरण तथा पुर्जे, ध्वनि रिकॉर्डर	516.53	322.24
8.	76	अल्युमिनियम, उसके लेख	316.54	291.59
9.	72	लोहा एवं स्टील	354.08	268.21
10.	38	विविध रासायनिक उत्पाद	242.44	244.57

Source:-Department of Commerce government of India.

इसी प्रकार से भारत जापान के बीच आयत की मदों की स्थिति तालिका में दर्ज है।

क्र.	**एच.एस.कोड**	**मदों का विवरण**	**धन राशि मिलियन डॉलर में वर्ष 2021-22**	**धन राशि मिलियन डॉलर में वर्ष 2022-23**
1.	84	परमाणु रिएक्टर, ब्वॉयलर मशीन	2702.62	2864.64
2.	28	बहुमूल्य धातुएं, दुर्लभ पृथ्वी, धातुओं के कार्बनिक, अकार्बनिक	1660.50	2152.34

3.	85	विद्युत मशीनरी, छवि और रिकॉर्डर	1317.65	1739.59
4.	72	लोहा और उससे बनी वस्तुएं	1011.55	1310.06
5.	74	तामा और उससे बनी वस्तुएं	1193.58	1284.05
6.	39	प्लास्टिक और उससे बनी वस्तुएं	1237.17	1218.56
7.	29	जैविक रसायन	776.88	876.46
8.	90	ऑप्टिकल, फोटोग्राफिक सिनेमैटोग्राफिक, मापता की जांच, चिकित्सा या चिकित्सा संस्थान	699.54	742.65
9.	87	रेलवे, टर्म्बे, स्टॉक, वाहन और हिस्से	762.9	734.22
10.	71	प्राकृतिक और सुसंस्कृत मोती, कीमती, कीमती, पत्थर, नकली आभूषण।	169.87	434.34

Source:-Department of Commerce government of India.

इस प्रकार कहा जा सकता है कि, भारत और जापान, के बीच, हुई आर्थिक साझेदारी समझौता, के तहत, दोनों देशों को, संयुक्त रूप से लाभ प्राप्त होगा।

निष्कर्ष

उपरोक्त विवरण के, आधार पर, कहा जा सकता है कि, वर्तमान में विभिन्न देशों के बीच, बढ़ती हुई आर्थिक साझेदारी समझौते, वास्तव में, अद्वितीय हैं क्योंकि इससे, एक तरफ तो, अर्थव्यवस्था का, विस्तार व विकास होता है, तो दूसरी तरफ, देश की, आर्थिक विकास दर शीर्ष पर पहुंच जाती है। इस दृष्टि से, भारत और जापान, के बीच, आर्थिक साझेदारी समझौते अद्भुत हैं। इसने

भारत के, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, सतत रूप से, वृद्धि की है, विदेशी पूंजी का, आगमन होने से, निवेश में, वृद्धि हुई है, जिससे रोजगार के, अनेकों अवसर प्राप्त हुए हैं।

भारत, के अनेक आर्थिक नीति-निर्माताओ और अर्थशास्त्रियों का, कहना है कि, वास्तव में, आर्थिक साझेदारी समझौते, भारतीय अर्थव्यवस्था में, आर्थिक दृष्टि से, एक इधन साबित हुए हैं, जिससे अर्थव्यवस्था, विश्व के, कई अन्य देशों की, तुलना में, कहीं अधिक, तेजी से अग्रणी रही है। यदि, यह साझेदारी, इसी तरह से, संचालित होती रही तो, वह दिन दूर नहीं, जब भारतीय अर्थव्यवस्था, विश्व में सबसे बड़ी, अर्थव्यवस्था बन जाएगी।

Reference:

1.Decoding India-UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement. (www.linkedin.com) 23, July 2022., https://www.linkedin.com/pules/decoding-india-uae-comprehensive-economic-partnership-agreement.

2.Economic Partnership Definition., https://www.lawinsider.com/dictionary/economic-partnership.

3.Rajaram, P., Raut and J.I., Jacov, (2008) Changing Paradigms of Ind-Japanese Relation:-Opportunity and Challenge, Indian Council for Research in International Relation., Working Paper Number 212, New Delhi.

4.David Ingram, "What is An Economic Partnership Agreement, https://smallbusiness.chron.com/economic-partnership-agreement-3888.html.

5.Seth, S. (2022) Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Definition., (www.investopedia.com) 29 September 2022., https://www.investopedia.com/terms/r/regional-comprehensive-economic-partnership-rcep.asp.

6.IBID.

7.What Do You Mean By Economic Partnership Agreement., (www.abip.org.br) 4 November 2022., https://www.abip.org.br/site/what-do-you-mean-by-economic-partnership-agreement.

8.IBID.

9.Fact Sheet Number 1 (March 2007) Understanding The Economic Partnership Agreement., (EPAs) South Center, Analytical Note SC/AN/TDP/EPA/1 Original:-English March 2007, Geneva, Switzerland.

10.Zamfir, L. (2018) An Overview of The EU-ACP Countries Economic Partnership Agreement:-Building A New Trade Relationship., European Parliamentry Research Service., (EPRS) PE 625.102-July 2018.

11.To See The Reference Number (7).

12.MOFA, Overview of Japans ODA to India, June 2011, Retrieved From https//www.in emb-japan.go.jp/japan-india-relation/oda-eng-june2011.pdf. On 2 September 2015, MOFA, India n.d. Retireved From, https://www.mofa.go.jp/policy/oda/data/pdf/india.pdf On 2 September 2015.

13.Authors Estimates From Japanese Government Data.

14.CEPA With Japan., Press Information Bureau., Government of India., Ministry of Commerce and Industry., 5 August 2013, https://pib.gov.in/newssite/printrelease.aspx?relid=97633.

15.Exchange Rate As Per Average of Annual Year 2010-2011 (1 USD=45:57 Rupees),rbi.org.in/scripts/publicationview.

16.Yamanouchi , T (2000) India Through Japanese Eyes, Sterling publication United, New Delhi.

17.To See The Reference Number (14).

18.Ram. Upendra, Das (January 2014) India-Japan comprehensive economic partnership agreement,:- some implication for East Asian economic regionalism and RCEP, RIS discussion paper- 186, January 2014.

19.government of India (2012) Bilateral Development Corporation with Japan, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, government of India, http://finance. nic.in/ the-ministry/dept-eco-affairs/japan/japan-index .asp.

20.Nataraj, G.(2010) India-Japan investment relation.:- Trends and Prospect., ICRIER, working paper number 245, January.

21.Comprehensive economic partnership agreement (CEPA) between India and Japan comes into Force. The Economic Times (newspaper) 1, August 2011.

22.India-Japan Commercial relations., Embassy of India, Tokyo, Japan (www.indembassy- tokyo.gov.in) 7th, March 2024., https://www.Indembassy-tokyo.gov.in/eoityo- pages/NJA.

23.IBID.